'सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य शीघ्र पूरा करें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली

जयपुर, 14 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारी सरकार आमजन के समग्र कल्याण के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनकल्याण से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च वरीयता देते हुए, इनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में ऊर्जा विभाग, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, पीएचईडी, स्वायत्त शासन, जल संसाधन एवं नगरीय विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग प्रत्येक विकास कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बना कर कार्यों को शीघ्र पूरा करें, जिससे आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

- समीक्षा बैठक में ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, पीएचईडी, स्वायत्त शासन, जल संसाधन एवं नगरीय विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बना कर कार्यों को शीघ्र पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपर स्पैशिएलिटी चिकित्सा को नये आयाम देने के लिए, आरयूएचएस का उन्नयन कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) की स्थापना की जाएगी। इस केन्द्र पर आयुष विंग, वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं देने के लिए एकीकृत केन्द्र, थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएं विकसित होंगी।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न 132 केवी तथा 33 केवी जीएसएस निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रांसफार्मर के आस-पास के क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ-साथ, तारबंदी की जाए एवं इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए। इसी के साथ, मुख्यमंत्री ने सांगानेर के जैन मंदिर, सांगा बाबा मंदिर तथा हनुमानजी मंदिर के आस-पास सौन्दर्यीकरण का कार्य करवाने को कहा। उन्होंने दुर्गापुरा उद्यानिकी महाविद्यालय में बालिका छात्रावास एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा प्रतापनगर में खेल स्टेडियम के निर्माण को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

जस्टिस गवई ने सीजेआई के पद की शपथ ली

नयी दिल्ली, 14 मई। न्यायमूर्ति बी आर गवई ने बुधवार को यहां उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे इस वर्ष 23 नवंबर तक इस पद पर रहेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलायी। उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है, जो कल मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हो गये। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जे पी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीश और कुछ पूर्व न्यायाधीश समेत, कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

- शपथ ग्रहण कार्यक्रम में गवई के परिजन भी थे। गवई ने शपथ लेने के बाद अपनी माँ के पैर छुए।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति गवई की पत्नी, मां तथा परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। शपथ ग्रहण करने के बाद, सबसे पहले उन्होंने अपनी मां के पैर छुए।

'बलूचिस्तान ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन ताकतों के लिए अवसर पैदा करता है जो, आपदा अवसर ढूंढ़ती हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत इस स्थिति का गहराई से अध्ययन करेगा और फिर कोई निर्णय या कार्रवाई करेगा।

'कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं'

सचिन पायलट ने, ट्रंप के आतंकवाद पर एक भी शब्द नहीं कहने पर आपत्ति जताई

जयपुर, 14 मई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज बुधवार को अपने निवास पर पत्रकारों से वार्ता की। मीडिया से रूबरू होते हुए, सचिन पायलट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कश्मीर पर दिए बयानों और कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्यप्रदेश के मंत्री के बयानों को लेकर केन्द्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। पायलट कहा कि हमारे दोनों बहादुर योद्धा कर्नल कुरैशी, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कुछ दिन पहले देश को सेना के ऑपरेशन के बारे में जिस कुशलता से जानकारी दी, उसके लिए हम सबको भारतीय होने पर उन पर फ़ख्र है। पायलट ने कहा, जिस तरह मध्यप्रदेश के मंत्री ने टिप्पणी की , उसके बाद अब उनको मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। हमारी वीर कर्नल कुरैशी जी, जिनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है, उनके प्रति जो अनादर दिखाया है, वह बिल्कुल अस्वीकार्य है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने निवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्यप्रदेश के मंत्री के बयानों को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है।

पायलट ने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल सऊदी अरब में फिर से सीज़फायर का जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति व्यापार वाला बयान बार- बार क्यों दे रहे हैं। इसको लेकर उसका सीधे तौर पर सरकार ने खंडन नहीं किया। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति बढ़ाने को लेकर बात कही, उन्होंने आतंकवाद को लेकर एक शब्द नहीं कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल रहे हैं जो ठीक नहीं, भारत की तुलना चीन से होती थी, भारत की तुलना कभी भी पाकिस्तान से हो ही नहीं सकती। आश्चर्य की बात है कि ट्रंप कश्मीर मसले को बीच में ले आए, सरकार को इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए। पीओके को हमें वापस लेना है । यह प्रस्ताव संसद में दोबारा पारित किया जाए। सन् 1994 में पारित इस प्रस्ताव को अब दोबारा से पारित करने का मौका है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। सरकार से मांग है कि चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरा देश एकजुट है।

- पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आतंकवाद और सीज़फायर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की माँग की।

पायलट ने कहा, भारत की तमाम जनता और राजनीतिक दल मानते हैं कि हमने बहुत आतंकी हमले झेल लिए। किन शर्तों पर सीज़फायर हुआ है। पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो लोन मिला , क्या उस पैसे का दुरुपयोग करके फिर से आतंक को बढ़ावा देने का काम पाक नहीं करेगा।। पाकिस्तान पर कितना विश्वास किया जा सकता है । सीज़फायर के तुरंत बाद गोलाबारी हुई, कैसे विश्वास करें। आतंक को खत्म करने के मुद्दे पर भारत एक है, केन्द्र सरकार को जनता और विपक्ष का पूरा समर्थन मिला। पहलगाम के आतंकियों का क्या स्टेटस है । सेना के शौर्य पर हम सबको गर्व है, सभी एक मत हैं। अचानक सीज़फायर होना अप्रत्याशित है। सीज़फायर अमेरिका द्वारा करना भी अप्रत्याशित है। उन्होंने आगे कहा कि सेना द्वारा बहुत ही सावधानी और संयम के साथ एयरस्ट्राइक की गई। इसमें किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। भारत की सेना ने फिर अपना शौर्य दिखाया। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है।

नाबालिग को बंधक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभियुक्त उसका मुंह बंद कर विधानसभा के पास एक कैफे में भी लेकर जाता और दो अन्य लड़कों से भी दुष्कर्म कराता। अभियुक्त ने उसे धमकी दी कि उसका मामा पार्षद और एमएलए है। इसलिए वह किसी से नहीं डरता। रिपोर्ट में कहा गया कि 13 अगस्त को मोनू एक अन्य लड़की को उसके कमरे में लाया था। वहीं, सुबह पुलिस आकर उस लड़की को अपने साथ ले गई। वहीं जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि होटल संचालक श्रवण सिंह ने भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। इस पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व आईएएस संधू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनकी ओर से कहा गया कि टोडी रामजानीपुरा की 3.43 हेक्टर जमीन के एकल पट्टे के लिए पूर्व में जेडीए में आवेदन किया गया था। जमीन तय सीमा से अधिक होने के कारण जेडीए ने साल 2005 में प्रकरण राज्य सरकार को भेजा था, जिस पर राज्य सरकार ने पट्टा देने से इनकार कर दिया। वहीं, साल 2009 में आवेदन होने पर जेडीए ने मामले को पुन: राज्य सरकार के समक्ष भेजा। राज्य सरकार ने साल 2011 में पट्टा जारी कर दिया। वहीं, तकनीकी कारणों के चलते साल 2013 में एकल पट्टा निरस्त कर दिया गया। संधू की ओर से कहा गया कि पट्टा निरस्त होने के बाद रामशरण सिंह ने साल 2014 में एसीबी में शिकायत की थी। ऐसे में कोई अपराध नहीं बनता है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी एसीबी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा वापस लेने की बात कही थी। इसलिए प्रकरण की कार्रवाई को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं।

उदयपुर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया जाता है जो करीब ढाई हजार करोड़ से ज्यादा लागत का है। सुराणा ने कहा कि प्रोससर्स समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि तुर्किये से आने वाले मार्बल को हमने रोक दिया है। इससे तुर्किये के आर्थिक चक्र पर भी इसका असर दिखेगा।

उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के महासचिव हितेश पटेल ने बताया कि उदयपुर के पचास से ज्यादा बड़े व्यवसायी तुर्किये से बड़ी तादाद में मार्बल आयात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसका बहिष्कार करने का फैसला लिया हैं।

सभी एकजुट हैं और इस बात पर अडिग हैं कि जब तक तुर्किये द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करना बंद नहीं होगा, तब तक तुर्की का बहिष्कार जारी रहेगा। व्यापारियों ने कहा कि तुर्किये से हम 70 प्रतिशत मार्बल मंगवाते है और अब हमने निर्णय कर स्वेच्छा से वहां से आने वाले मार्बल को मंगवाने से मना कर दिया है।

सालाना अच्छा व्यापार हो रहा था लेकिन अब इसका बड़ा असर पड़ेगा और तुर्किये के व्यापार को भी बड़ा धक्का लगेगा।

सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी: मंत्री पर एफआईआर के आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के महाधिवक्ता को मंत्री विजय शाह पर एफआईआर करने के आदेश दिए

जबलपुर, 14 मई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में आपत्तिजनक बयान देने से जुड़े प्रकरण में आज राज्य के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए और कहा कि यह कार्य आज यानी बुधवार शाम तक हो जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय की युगल पीठ के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला ने इस मामले में मीडिया में आयी खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को ये आदेश दिए। अदालत ने महाधिवक्ता से कहा कि इस आदेश के संबंध में तत्काल राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अवगत कराया जाए और इसका क्रियान्वयन नहीं होने पर इस मामले में अवमानना संबंधी कार्यवाही भी की जा सकती है।

- कोर्ट ने बुधवार को दिन में आदेश देते हुए बुधवार शाम तक एफआईआर करने और हाईकोर्ट को रिपोर्ट करने के आदेश दिए।
- मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 (1) (बी) और 197 (1) (सी) के तहत एफआईआर करने के आदेश दिए। इससे मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई है उनकी कुर्सी भी जा सकती है।

अदालत ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये धाराएं देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने जैसे कृत्यों से संबंधित हैं। अदालत के इस महत्वपूर्ण आदेश के बाद मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। माना जा रहा है कि अब राज्य पुलिस अदालत के आदेश के अनुरूप वैधानिक कदम उठाएगी। इसके साथ ही उनका मंत्री पद भी जाना तय माना जा रहा है। वे अक्सर विवादास्पद बयान देते रहते हैं।

मंगलवार से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इंदौर जिले के महू विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम का बताया गया है। उसमें वे सार्वजनिक मंच से संबोधन दे रहे हैं और इस अवसर पर एक महिला नेता समेत अनेक लोग मौजूद रहे। मंत्री शाह कहते हुए सुने जा रहे हैं, ...जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे...हमने उन्हीं की बहन भेजकर.....। मंत्री शाह इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए। इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान में लेने के साथ ही प्रदेश भाजपा इकाई ने मंत्री को फटकारा। इसके बाद मंत्री ने माफी भी मांगी, लेकिन मीडिया के सामने माफी मांगने संबंधी बयान के बाद उनका हंसते हुए वीडियो भी वायरल हो गया। यह वीडियो भी मंत्री की किरकिरी का कारण बन गया।

अजय कुमार यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त

नयी दिल्ली, 14 मई। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत, डॉ. अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

- अजय कुमार वर्ष 2019 से 2022 तक रक्षा सचिव के पद पर काम कर चुके हैं।

आदेश के अनुसार, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अजय कुमार का कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होगा। उनकी नियुक्ति की अवधि संविधान के अनुच्छेद 316(2) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी और सेवा की शर्तें समय-समय पर संशोधित यूपीएससी (सदस्य) विनियम, 1969 द्वारा शासित होंगी।

बुधवार को कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरएसएस के अंदर, संकटकाल में मोदी के नेतृत्व पर गंभीर संदेह है तथा यह सोच तेजी से बढ़ती जा रही है कि वे ट्रंप का सामना नहीं कर सकते तथा संकट के समय देश को नहीं संभाल सकते। देखना यह है कि यह स्थिति क्या रूप लेती है, लेकिन जवाब न मिलने की स्थिति में, आक्रोश बढ़ रहा है।

प्रधामंत्री ने 25 मई को एनडीए मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई है, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाना और उसमें उपस्थिति होना उन्होंने उचित नहीं समझा है। एक आरएसएस समर्थक ने कहा है, "जे.पी. नड्डा हमेशा तो भाजपा अध्यक्ष पद पर रह नहीं सकते, इसलिए जब नये भाजपा अध्यक्ष की घोषणा होगी, उस समय प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में भी कानाफूसी शुरु हो सकती है।

बिना विभागीय जाँच के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश नरेश पाल देवानिया की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि विभागीय जांच के बिना कर्मचारी को सेवा से हटाना अनुचित और उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिका में अधिवक्ता मोविल जीनवाल ने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 23 मार्च 2021 को छेड़छाड़ के मामले में एक एफआईआर महिला पुलिस थाना, भिवाड़ी में दर्ज हुई थी। एसपी ने बिना किसी जांच के, उसी दिन याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने इसे अपीलेट अथॉरिटी में चुनौती दी, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने बिना तथ्य देखे 9 सितंबर, 2021 को उसकी अपील खारिज कर दी। इस कार्रवाई को याचिका में चुनौती देते हुए कहा गया कि विभाग की कार्रवाई संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। इसके अलावा एक सरकारी कर्मचारी को बिना सही जांच के दंडित भी नहीं किया जा सकता। मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर पीड़िता के साथ समझौता करने व उसके ही आवेदन पर निचली अदालत से रद्द हो चुकी है, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए अपील खारिज कर दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को समस्त परिलाभ सहित सेवा में लेने को कहा है।

अनिता आनन्द के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अलगाववादी ऐजेण्डा को बढ़ावा देने के लिए न किया जाए। यह एक नाज़ुक और संवेदनशील रास्ता होगा, लेकिन आनंद अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और राजनीतिक व्यवहारिकता के कारण इसे अपने पूर्ववर्तियों से बेहतर संभाल सकती हैं।

यदि कुशलता और परिपक्वता के साथ हैण्डल किया संभाला जाए, तो उनके कार्यकाल में रुकी हुई व्यापार वार्ताओं को पुनर्जीवित किया जा सकता है, प्रवासन चैनलों को फिर से खोला जा सकता है, तथा शिक्षा, टैक्नॉलजी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। अनिता आनंद, प्रवासी समुदाय से जुड़े उन मुद्दों को भी गैर-राजनीतिक बनाने में मददगार हो सकती हैं, जो लंबे समय से ऑटवा और नई दिल्ली के बीच, खुली बातचीत और वार्ता में विश्वास की कमी के कारण जटिल होते जा रहे हैं।

तथापि, व्यापक संदर्भ को समझना आवश्यक है। कैनडा-भारत संबंधों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगे आरोपों के बाद पैदा हुए राजनयिक तनावों के कारण। आनंद ने एक ओर कैनडा की संप्रभुता और कानून के शासन की रक्षा के महत्व पर जोर दिया है, तो दूसरी ओर उन्होंने अपनी भारतीय जड़ों को भी स्वीकार किया है, जिससे उनकी विदेश नीति में संतुलन और समझदारी की झलक मिलती है।

फिर भी, आशाओं को यथार्थवाद के साथ जोड़कर देखना जरूरी है। प्रवासी उग्रवाद, भू-राजनीतिक मतभेद और पारस्परिक अविश्वास जैसी मूल समस्याएं एक रात में खत्म नहीं होंगी। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आनंद को कैनडा की सरकार में कितना स्वतंत्र काम करने का मौका मिलता है और नई दिल्ली कितनी गंभीरता से फिर से जुड़ने को तैयार है।

यह बात स्पष्ट है कि आनंद एक नया राजनयिक चेहरा हैं, जो टूडो-निज्जर विवाद से अप्रभावित हैं। उनकी नियुक्ति कैनडा और भारत के लिए, वर्षों में पहला और संभवत: सबसे अच्छा अवसर है कि दोनों देश तनावों से आगे बढ़ें और एक व्यावहारिक, परस्पर लाभकारी साझेदारी की ओर अग्रसर हों।

इस अवसर का उपयोग किया जाएगा या इसे गंवा दिया जाएगा - इससे तय होगा कि विश्व के सबसे जटिल द्विपक्षीय संबंधों में से एक का भविष्य क्या होगा।

पाकिस्तान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ नियमित फ्लैग मीटिंग और अन्य संचार चैनलों के माध्यम से बीएसएफ के लगातार प्रयासों से शॉ की वापसी संभव हो पायी है।

चीन के अधिकारियों ने भारत व पाकिस्तान के राजदूतों से मीटिंग की

बीजिंग/इस्लामाबाद/नयी दिल्ली, 14 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद, चीन के शीर्ष अधिकारियों ने बीजिंग में भारतीय और पाकिस्तानी राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के महानिदेशक लियू जिनसोंग ने सोमवार को चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने चीन-भारत संबंधों और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मंगलवार को चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेदोंग ने पाकिस्तान के राजदूत खलील हाशमी से उनके अनुरोध पर मुलाकात की। वेदोंग और पाक राजदूत की मुलाकात में दोनों ने चीन-पाक संबंधों और क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय हालात पर चर्चा की। वेदोंग ने भारत-पाक के बीच पूर्ण और स्थायी संघर्ष-विराम का समर्थन करते हुए मतभेद सुलझाने की अपील की और क्षेत्रीय शांति में चीन की रचनात्मक भूमिका जारी रखने की बात कही।

- चीन के टॉप अफसरों ने दोनों देशों के राजदूतों से अलग-अलग बात की।

अरब लीग ने आतंकवाद पर भारत का समर्थन किया

अरब लीग के राजदूत युसूफ मोहम्मद जमील ने एक बयान जारी कर भारत के प्रति समर्थन जताया

नयी दिल्ली, 14 मई। अरब लीग के नयी दिल्ली स्थित राजनयिक मिशन के प्रमुख यूसुफ मोहम्मद जमील ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद का खात्मा करने के लिए भारत और अरब क्षेत्र के देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने आतंकवाद को विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा बताया है।

राजदूत जमील ने एक बयान में कहा, देश के बाहर से संचालित आतंकवाद और ऐसे अन्य खतरों से निपटने के मामले में हमारी सोच एक जैसी है। हम खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त पहल के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा के वातावरण को मजबूत बनाना है।

अरब लीग के राजदूत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि यह कृत्य न केवल बर्बर, बल्कि अमानवीय भी है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकने का स्वागत किया और कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों के बीच सैनिक कार्रवाई का रुकना बहुत ही जरूरी था। जमील ने कहा, हम इस पक्ष के हैं कि दोनों देशों के बीच विवाद के समाधान के लिए बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों को अपना जाय ।

- राजदूत जमील ने एक बयान में कहा कि देश के बाहर से संचालित आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए हमारी सोच एक जैसी है।

ऐसा दृष्टिकोण न केवल राजनीतिक स्थिरता, बल्कि इस क्षेत्र के देशों की आर्थिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है।

जमील ने उम्मीद जताई कि अरब-भारत मंत्रीस्तरीय संचालन फोरम की एक बैठक निकट भविष्य में आयोजित की जाएगी और इससे दोनों पक्षों के बीच सहयोग को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कह कि अरब लीग के देशों के साथ भारत के संबंधों को अपेक्षित गति देने के लिए इस तरह की उच्च स्तरीय सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा, हमें इन बैठकों में राजनीतिक मामलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा संबंधी मामलों को भी इनमें शामिल करना चाहिए।

चीन-बाँग्लादेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्दरुनी भूगोल के उल्लेख की तार्किकता पर सवाल खड़े किये हैं। उन्होंने कहा, "दिलचस्प बात यह है कि यूनुस चीन से निवेश की सार्वजनिक रुप से अपील इस आधार पर कर रहे हैं कि (भारत के) सात उत्तर-पूर्वी राज्य लैंडलॉक्ड हैं। लेकिन यह कहने का आखिर औचित्य क्या है कि ये सात भारतीय राज्य लैंडलॉक्ड हैं?"

मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए

बीजापुर, 14 मई। छत्तीसगढ़ के करेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन में 31 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया और उनके 150 से ज्यादा बंकरों को भी नष्ट कर दिया। मारे गए माओवादियों पर 1.72 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किये गये।

इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए हैं। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक जीपी सिंह और छत्तीसगढ राज्य के पुलिस महानिदेशक अरूणदेव गौतम ने बुधवार को बताया कि बीजापुर के करेंगुट्टा की पहाड़ी में 21 दिनों तक चलाये गये नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान कुल 21 मुठभेड़ों में 31 माओवादी मारे गए। दोनों अधिकारियों ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को यह बहुत बड़ी सफलता मिली है। मारे गये 28 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिनपर एक करोड़ बहत्तर लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा पुलिस ने विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किया।

- इन नक्सलियों पर 1.72 करोड़ रु. का ईनाम था।
- सुरक्षाबलों ने छत्तीसगढ़ की करेगुट्टा पहाड़ी में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के तहत यह कार्यवाही की।

सिंह और गौतम ने आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908